



### संक्षिप्त समाचार

राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के विधिक सलाहकार को दी गई भावभीनी विदाई



**रायपुर (विश्व परिवार)**। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन के विधिक सलाहकार श्री राजेश श्रीवास्तव अपनी अधिकारियों के सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इस असर पर उन्होंने आज राजभवन में भावभीनी विदाई दी गई। राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन ने उनके उन्नचल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्री श्रीवास्तव ने राजभवन में पदस्थापन के दौरान अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता पूर्वक किया है। किसी भी फाइल के निरकरण में कृती पहलूओं की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। विधिक सलाहकार के पद पर रहे हुए श्री श्रीवास्तव ने दक्षता पूर्वक अपना कार्य करते हुए फाइलों के सही तरीके से निरकरण में सहयोग किया। भगवान् जाग्रात से प्रार्थना है कि उनका भावी जीवन सुखमय रहे। राज्यपाल ने श्री श्रीवास्तव के शाल और स्मृति चिह्न देकर समाप्ति किया। राज्यपाल के सचिव श्रीमती देवी ने निरकरण में सहयोग किया। भगवान् जाग्रात से प्रार्थना है कि उनका भावी जीवन सुखमय रहे। राज्यपाल ने श्री श्रीवास्तव के शाल और स्मृति चिह्न देकर समाप्ति किया। राज्यपाल के सचिव श्रीमती देवी ने श्री श्रीवास्तव के सुखद भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप सचिव श्रीमती देवी ने तोमां सहित राजभवन के अन्न अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

**किसान यूनियन को देशद्रोही बताने वाले भाजपा नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो : तेजराम विद्रोही**

**राजिम (विश्व परिवार)**। देश के प्रमुख किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) जिसने देश के तात्पर्य सरकारों तथा सभी वर्गों का समाजान निकालने में सक्षम है। नारानामों में चल रहे झाड़ेश संघर्ष समिति के आठ स्त्रीयों अंदोलन का भारतीय किसान यूनियन ने समर्थन दिया है जिससे एक भाजपा नेता द्वारा राष्ट्रद्रोह कहा गया है। यह गाली सिर्फ किसान वर्ग को नहीं बल्कि देश के अदिवासियों, शांतियों, दलितों, पिछड़े वर्ग को दी गयी है जिनकी आवाज करोरपोरेट दलाल एवं शोषणकारी के लोग तक नहीं पहुँचने देना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन देश भर के सभी अदिवासियों, शांतियों, पिछड़े वर्गों की आवाज प्रमुखता से दिल्ली में चले किसान अंदोलन में शामिल किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही, घुंडे, बदमाश कहा गया और अब यह छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है। सनाधारी पार्टी के लोगों द्वारा किसानों को रुद्ध करवाने के लिए दिल्ली में चले किसान अंदोलन में शामिल किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, देशद्रोही, घुंडे, बदमाश कहा गया पर बायरल किया जा रहा है जिसका संदेश का स्क्रीन शॉट संलग्न है।

### एमडी अविनाश मिश्रा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का किया निरीक्षण 247 वाटर सप्लाई, अंडर ग्राउंड केबलिंग, महाराजबंध एसटीपी प्रोजेक्ट का लिया जायजा

केबलिंग के दौरान क्षितिग्रस्त सड़कों को तुरत दुर्लक्ष करने के निर्देश

**रायपुर (विश्व परिवार)**। नारानिगम कमिशनर एवं रायपुर स्मार्ट सिटी के एम डी श्री अविनाश मिश्रा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के ओचक निरीक्षण किया इस दौरान सहायक कलेक्टर सुधी अनुपमा अनंद सहित स्मार्ट सिटी के तकनीकी अधिकारी भी साथ थे।

एमडी श्री मिश्रा ने निरीक्षण



नगर चौक से पुराणी बस्ती तक अंडरग्राउंड केबलिंग की जानकारी भी ली और यहाँ स्ट्रैट लाइट पोल जल्द लगाने का निर्देश दिया। 247 जल प्रदाय हेतु वाटर सप्लाई के निरीक्षण के लिए श्री मिश्रा आमापारा बजरंग नगर, मोदहापारा भी पहुँचे और रखवायियों से सीधे जानकारी भी ली प्राप्तिलाल बिछाने के दौरान क्षितिग्रस्त हुई सड़क तक ताल दुर्लक्ष करने उन्होंने कार्य एजेंसी से कहा।

निरीक्षण भ्रमण के दौरान

भ्रमण के दौरान बृद्धतालावा स्थित पुराने धरना स्थल में संचालित सौंदर्यकरण कार्य की प्रगति की जानकारी भी ली और शोध कार्य पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि श्री श्रीवास्तव ने राजभवन में पदस्थापन के दौरान अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता पूर्वक किया है। किसी भी फाइल के निरकरण में कृती पहलूओं की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। विधिक सलाहकार के पद पर रहे हुए श्री श्रीवास्तव ने उनके उन्नचल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि श्री श्रीवास्तव ने राजभवन में पदस्थापन के दौरान अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता पूर्वक किया है।

पर्यावरण संरक्षण एवं नये अमृत सरोवर पर जौर, मैराथन बैठक लेकर पंचायत विभाग के कामकाज की समीक्षा

**बलौदाबाजार (विश्व परिवार)**। कलेक्टर दीपक सोनी ने सिमगा विकासखंड के अंतर्गत नारानीय निकाय के पर्षदों, अध्यक्षों, जनपद पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों सहित संपर्च, उपरायरं एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनसे रूबरू हुए। उन्होंने सभी कार्यों का विवरण किया और शोध कार्य की जानकारी भी ली है। उन्होंने बहुत सजग रहने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप सचिव श्रीमती देवी ने तोमां सहित राजभवन के अन्न अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सजग रहने की अपील की, बेहतर कार्ययोजना के साथ ग्राम विकास में निभाएं सक्रिय सहभागिता

एसटीपी निर्माण कार्य के प्रगति की भी उन्होंने धरना स्थल में संचालित सौंदर्यकरण कार्य की प्रगति की जानकारी भी ली। यहाँ पाथ-वे, स्ट्रैट लाइट जैसे सभी कार्य जल्द पूरा करने निर्देश भी दिया है।

जोन कमिशनर श्री राकेश शर्मा स्मार्ट सिटी के उप-प्रबंधक श्री संजय अग्रवाल, श्री अमित प्रेमेंट गेटवे डेविल कार्ड, क्रैंडिट कार्ड और इंटररेट वैंकिंग (टेक्स के दौरान क्षितिग्रस्त हुई सड़क तक ताल दुर्लक्ष करने उन्होंने कार्य एजेंसी से कहा।

निरीक्षण भ्रमण के दौरान

एसटीपी निर्माण कार्य के प्रगति की जानकारी भी ली और शोध कार्य पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि श्री श्रीवास्तव ने राजभवन में पदस्थापन के दौरान अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता पूर्वक किया है।

पर्यावरण संरक्षण एवं नये अमृत सरोवर पर जौर, मैराथन बैठक लेकर पंचायत विभाग के कामकाज की समीक्षा

**बलौदाबाजार (विश्व परिवार)**। कलेक्टर दीपक सोनी ने सिमगा विकासखंड के अंतर्गत नारानीय निकाय के पर्षदों, अध्यक्षों, जनपद पंचायत सदस्यों सहित संपर्च, उपरायरं एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनसे रूबरू हुए। उन्होंने सभी कार्यों का विवरण किया और शोध कार्य की जानकारी भी ली है। उन्होंने बहुत सजग रहने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप सचिव श्रीमती देवी ने तोमां सहित राजभवन के अन्न अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सजग रहने की अपील की, बेहतर कार्ययोजना के साथ ग्राम विकास में निभाएं सक्रिय सहभागिता

एसटीपी निर्माण कार्य के प्रगति की जानकारी भी ली। यहाँ पाथ-वे, स्ट्रैट लाइट जैसे सभी कार्य जल्द पूरा करने निर्देश भी दिया है।

जोन कमिशनर श्री राकेश शर्मा स्मार्ट सिटी के उप-प्रबंधक श्री संजय अग्रवाल, श्री अमित प्रेमेंट गेटवे डेविल कार्ड, क्रैंडिट कार्ड और इंटररेट वैंकिंग (टेक्स के दौरान क्षितिग्रस्त हुई सड़क तक ताल दुर्लक्ष करने उन्होंने कार्य एजेंसी से कहा।

निरीक्षण भ्रमण के दौरान

एसटीपी निर्माण कार्य के प्रगति की जानकारी भी ली और शोध कार्य पूरा करने के लिए उन्होंने कहा कि श्री श्रीवास्तव ने राजभवन में पदस्थापन के दौरान अपने दायित्वों का निर्वहन कुशलता पूर्वक किया है।

पर्यावरण संरक्षण एवं नये अमृत सरोवर पर जौर, मैराथन बैठक लेकर पंचायत विभाग के कामकाज की समीक्षा

**बलौदाबाजार (विश्व परिवार)**। कलेक्टर दीपक सोनी ने सिमगा विकासखंड के अंतर्गत नारानीय निकाय के पर्षदों, अध्यक्षों, जनपद पंचायत सदस्यों सहित संपर्च, उपरायरं एवं अन्य जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनसे रूबरू हुए। उन्होंने सभी कार्यों का विवरण किया और शोध कार्य की जानकारी भी ली है। उन्होंने बहुत सजग रहने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप सचिव श्रीमती देवी ने तोमां सहित राजभवन के अन्न अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर सजग रहने की अपील की, बेहतर कार्ययोजना के साथ ग्राम विकास में निभाएं सक्रिय सहभागिता

एसटीपी निर्माण कार्य के प्रगति की जानकारी भी ली। यहाँ पाथ-वे, स्ट्रैट लाइट जैसे सभी कार्य जल्द पूरा करने निर्देश भी दिया है।

जोन कमिशनर श्री राकेश शर्मा स्मार्ट सिटी के उप-प्रबं



# संपादकीय रोजगार के सवाल पर राहत कितनी

## कारोबारी सुगमता का ध्यान

जीएसटी परिषद की बैठक में शनिवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद जीएसटी परिषद की इस पहली बैठक में रेलवे प्लेटफार्म टिकट, विश्राम कक्ष और प्रतीक्षालय सुविधाओं को जीएसटी मुक्त करने के महत्वपूर्ण फैसले के साथ ही सभी तरह के दूध के डिब्बों पर 12 फीसद की एक समान जीएसटी दर रखने का प्रस्ताव किया गया। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबंधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अनुपालन बोझ कम करने और करदाताओं को राहत देने की गरज से भी कई सिफारिश की गई। कोशिश है कि कारोबारी सुगमता के लिए व्यवसायों के लिए प्रक्रियात्मक जटिलताएं कम की जाएं। परिषद ने जीएसटी पंजीकरण आवेदकों के लिए बायोमिट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण के चरणबद्ध रोलआउट की सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी रिमांड नोटिस पर व्याज जुर्माना माफी की भी सिफारिश है। यह धारा उन मामलों से संबंधित है जिनमें धोखाधड़ी, दमन या गलतबयानी शामिल नहीं हैं। जो करदाता 31 मार्च, 2025 तक नोटिस में मांगी गई पूरी कर राशि का भुगतान करते हैं, उन्हें इस छूट से लाभ होगा। किसी चालान या डेबिट नोट पर इनुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने संबंधी मंजूरी भी दी जा रही है। छोटे करदाताओं को भी इस रूप में राहत मिलने वाली है कि वित्त वर्ष 2024-25 और उसके बाद के वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 20 अप्रैल से बढ़ा कर 30 जून की जाएगी। परिषद ने स्पष्ट किया है कि सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12 फीसद की एक समान जीएसटी दर लागू होगी। दूध के सभी डिब्बों पर उनकी सामग्री (स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम) की परवाह किए बिना एक समान दर 12 फीसद की सिफारिश की गई है हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों की अरसे से मांग को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के कार्टन बक्सों और नालीदार व गैर-नालीदार कागज या पेपरबोर्ड, दोनों से बने उत्पादों के लिए 12 फीसद जीएसटी का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के तहत लाने की सरकार की मंशा भी दोहराई। दरअसल, सिफारिशों में कारोबारी सुगमता को ध्यान में रखा गया है।

आलोक जोशी

लाकसभा चुनाव के नतीजों के बाद स लगता है कि रोजगार पर एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। सरकार के आलोचकों को लगता है कि बेरोजगारों का गुस्सा ही चुनाव नतीजों में सामने आया है। जाहिर है, सरकारी पक्ष भी इस तरफ से कान बंद करके नहीं बैठ सकता। खास बात यह है कि तमाम परेशानियों के बावजूद भारत लगातार दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और, इस बात पर तमाम विद्वान एकमत हैं कि आने वाले कम से कम दस-पंद्रह साल तक भारत में तरकी की रफ्तार इतनी या इससे तेज ही रहने वाली है। ऐसे में, नौजवानों की उम्मीद भी बढ़ती है, लेकिन यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि रोजगार का मरलब नौकरी नहीं है, और सिर्फ सरकारी नौकरी तो कर्तव्य नहीं। जीडीपी में आठ प्रतिशत की जबर्दस्त बढ़त दर हासिल करने के बाद भी बेरोजगारी भारत की बड़ी समस्याओं में एक बनी हुई है। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही यह बात साफ है कि राजनीतिक तालमेल से निपटने के बाद इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रोजगार का इंतजाम होगा। पिछले बुधवार को मत्रिमंडल की बैठक में जो फैसले हुए उनका व्योरा देते हुए रोजगार पर खास जोर दिखाई पड़ा। महाराष्ट्र के वधावन पोर्ट की मंजूरी के साथ ही बताया गया कि इससे 17 लाख रोजगार पैदा होंगे। 76,000 करोड़ रुपये के खर्च से बनने वाला यह बंदरगाह भारत की सबसे बड़ी इंप्रस्ट्रक्चर परियोजनाओं में से एक है। मगर इस खुशखबरी के साथ यह चिंता भी खड़ी हो जाती है कि तब करोड़ों रोजगार जुटाने के लिए कहां-कहां कितना-कितना खर्च करना पड़ेगा? भारत सरकार की पेरिसर्च यूनिट सरकारी कर्मचारियों और अप्सरों के वेतन-भत्तों पर खर्च का व्योरा जारी करती है। उसकी वेबसाइट पर आखिरी रिपोर्ट वित्त वर्ष 2020-21 की लगी है। इसके हिसाब से 1 मार्च, 2021 को केंद्र सरकार में सभी वर्गों के कुल 41,11,146 कर्मचारियों के पदों की मंजूरी थी, लेकिन इनमें से 9,95,803 पद



खाली थे। यानी, 24.22 प्रतिशत खाली पद भरे नहीं जा सके थे। उसके बाद का आंकड़ा अभी सामने नहीं है। मगर इस साल की शुरुआत में रेलवे भर्ती के मामले पर जैसा बवाल मचा, वह दिखाता है कि नौजवान कितने बेकरार हैं। अभी एक समाचार एंजेसी ने देश के जाने-माने अर्थशास्त्रियों से सवाल पूछे, तो उनमें से 91 फीसदी का जवाब था कि नई सरकार के लिए आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती रोजगार के सवाल का हल तलाशन ही होगा। उनके हिसाब से भी समस्या विकट हो रही है, क्योंकि तेज आर्थिक विकास के बावजूद उस अनुपात में रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की 'इंडिया इंडलॉग्यमेंट रिपोर्ट' ने पिछले बीस साल के दौरान भारत में रोजगार की तस्वीर खींचने की कोशिश की है। हालांकि, इन वर्षों में कोरोना काल के लगभग गर्त में गए साल भी शामिल हैं। पिछली भी, इसमें एक बड़ी चिंता सामने आती है। रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में देश की आबादी का लागभग 64 फीसदी हिस्सा 15 से 59 साल की उम्र के बीच है। इसी उम्र के लोगों को कामकाजी आबादी माना जाता है। हालांकि, इस पर विवाद हो सकता है, क्योंकि 18 से कम उम्र के लोगों को रोजगार में होना नहीं चाहिए और आजकल 60 पार करने के बाद भी कई लोग तरह-तरह के काम करते रहते हैं पिछली भी, यदि इसी परिभाषा को मान लें, तो सोन्नेवाली बात यह है कि 2011 में आबादी का 61 फीसदी हिस्सा ही ऐसे लोगों का था, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक, 2036 तक यह हिस्सेदारी बढ़कर 65 फीसदी हो जाएगी। हर साल 80 लाख से ज्यादा नौजवान इस बिरादरी का हिस्सा बन रहे हैं। इसमें थोड़ा और बारीकी से ज्ञानें, तो पता चलता है कि 2000 में जह आबादी के इस हिस्से में सिर्फ 18 फीसदी लोग पढ़े-लिखे थे, वहीं 2022 तक यह गिनती बढ़कर 35 फीसदी हो चुकी थी। जबकि, दूसरी तरफ इसी दौरान कमाइ कर रहे नौजवानों की गिनती 52 फीसदी से गिरकर 37 फीसदी पर पहुंच गई थी। इस रिपोर्ट में साफदिख रहा है कि बेरोजगारी का संकट मुख्यरूप से नौजवानों की समस्या है। 2022 में कुल बेरोजगारों में 82.9 प्रतिशत नौजवान थे, जबकि पढ़े-लिखे नौजवान इस बेरोजगारों की फैज का 65.7 फीसदी हिस्सा हो चुके थे। चिंता के ओर बढ़ाने वाला आंकड़ा यह है कि 12वीं क्लास य उससे ज्यादा पढ़ने के बाद भी जो लोग बेरोजगार हैं, उनमें से 76.7 फीसदी महिलाएं या लड़कियां थीं साफ है, ये सारे लोग सरकारी या निजी नौकरी के भरोसे तो हैं नहीं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं, जो

स्वरोजगार करते हैं और वे भी, जो अपने परिवार के कारोबार में हाथ बंटाते हैं। दीगर यह भी है कि भारत की आबादी का 65 प्रतिशत हिस्सा गांवों में रहता है और 47 फीसदी खेती या उससे जुड़े कामकाज के भरोसे है। यह जानकारी 2022 के आर्थिक सर्वेक्षण में थी। मगर अब बेरोजगारी की ज़दोजहद में सबसे बड़ी व कमज़ोर कड़ी है खेती के अलावा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले या काम की तलाश में लगे लोग। इन्हीं का हाल बताने के लिए सरकार का सांख्यिकी विभाग नियमित रूप से सर्वेक्षण करता रहता है। शहरी क्षेत्रों के लिए तिमाही रिपोर्ट आती है, जबकि गांवों के लिए सालाना। इसी महीने सरकार ने 2021-22 और 2022-23 के सालाना सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। 2022-23 की रिपोर्ट में बेरोजगारी की दर 3.2 प्रतिशत दिख रही है, यानी अमेरिका से भी कम, लेकिन इसी में 15 से 29 साल की उम्र के लोगों में यह 10 फीसदी के चिंताजनक स्तर पर दिख रही है। 2017-18 के आंकड़े से मिलाएं, तो पता चलता है कि यह 17.8 प्रतिशत की ऊँचाई से गिरकर 10 फीसदी पर आई है। जीड़ीपी में आठ प्रतिशत की जबर्दस्त बढ़त दर हासिल करने के बाद भी बेरोजगारी भारत की बड़ी समस्याओं में एक बनी हुई है। एनडाई सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही यह बात साफ है कि राजनीतिक तालमेल से निपटने के बाद इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती रोजगार का इंतजाम होगा। पिछले बुधवार को मर्टिमंडल की बैठक में जो फैसले हुए उनका ब्योरा देते हुए रोजगार पर खास जोर दिखाई पड़ा। महाराष्ट्र के विधान पोर्ट की मंजूरी के साथ ही बताया गया कि इससे 17 लाख रोजगार पैदा होंगे। 76,000 करोड़ रुपये के खर्च से बनने वाला यह बंदरगाह भारत की सबसे बड़ी इंप्रेस्ट्रक्टर परियोजनाओं में से एक है। मगर इस खुशखबरी के साथ यह चिंता भी खड़ी हो जाती है कि तब करोड़ों रोजगार जुटाने के लिए कहां-कहां कितना-कितना खर्च करना पड़ेगा? भारत सरकार की पेरिसर्च यूनिट सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के बेतन-भत्तों पर खर्च का ब्योरा जारी करती है। उसकी वेबसाइट पर आखिरी रिपोर्ट वित्त वर्ष 2020-21 की लगी है।

## विशेष लेख

## **आपातकाल में संघ की भूमिका महत्वपूर्ण अध्याय**

डा. प्रशांत बड्ढ्याल

भारतीय राजनीति में जब कभी भी लोकतात्रिक इतिहास का कलंकित अध्याय खोला जाएगा, तो वह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा सांविधानिक प्रवर्धनों की निर्मम हत्या कर देश में आपातकाल की घोषणा 25 जून की मध्यसत्री ही रहेगा। आपातकाल महज नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित करना एवं समाज में पुनः निरंकुश कानून को स्थापित करना भर नहीं था, बल्कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गांधी की एकत्रफा हार का प्रमुख कारण रहा। तत्पश्चात अपने हजारों राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया और सरकार के लिए खतरा माने जाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन संगठनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) एक प्रभावशाली संगठन था। इसके बाद जो हुआ, वह आरएसएस के इतिहास के सबसे उल्लेखनीय अध्यायों में से एक 'निष्क्रिय प्रतिरोध आंदोलन' था, जिसने प्रतिबंध की पुरजोर अवहेलना की और अपने संगठनात्मक ढाँचे को काफी हद तक अक्षुण्ण रखा और आपातकाल का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रतिरोध के शीर्ष पर संघ के तत्कालीन सरसंघचालक मधुकर दत्तात्रेय देवरस (बालासाहेब देवरस) थे। उहोंने अपनी गिरफ्तारी से पूर्व कार्यकालों और स्वयंसेवकों को संबोधित किया और कहा कि, 'इस असाधारण स्थिति में, स्वयं सेवक अपना संतुलन खोने के लिए बाध्य नहीं हैं। 26 जून, 1975 की सुबह जैसे ही आपातकाल की घोषणा की खबर पूरे भारत में फैली, देश में अविश्वास और भय की भावना फैल गई। आपातकाल का लागू होना राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक चुनौतियों और इंदिरा गांधी की बढ़ती सत्तावादी प्रवृत्तियों के दौर की

परिणति के रूप में आया। संघ, जो लंबे समय से गांधी की चुनिदा नीतियों की आलोचना करता रहा, आपातकाल की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर उनके प्रमुख नेताओं को घेर लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि यह संघ की दूरवर्षीता ही थी कि शीर्ष नेतृत्व ने इस तरह के कदम का पूर्वानुमान लगा लिया था। आपातकाल से कुछ समय पूर्व जैसे-जैसे राजनीतिक तनाव बढ़ा, बालासाहब देवरस और संघ के अन्य वरिष्ठ नेतृत्व ने आकस्मिक योजनाएं बनानी शुरू कर दी थीं। उन्हें ढूढ़ विश्वास था कि संगठन की यह तैयारी उस तूफान का अपनी क्षमतापूर्वक सामना करने में महत्वपूर्ण साबित होगी जो इसे घेरने वाला था और जनकल्याण हेतु कार्य में विघ्न उत्पन्न करने वाला था। संघ के वरिष्ठ प्रचारक और लोक संघर्ष समिति के संयोजक, नानाजी देशमुख (जिन्होंने 1977 में जनता पार्टी के बैनर तले विपक्ष को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई) और के. एस. सुदर्शन ने भी पत्रों के माध्यम से विभिन्न संगठनों के साथ भी संवाद किया। संघ पर सरकार की कार्रवाई त्वरित और कठोर थी। शीर्ष नेतृत्व से लेकर स्थानीय स्तर के हजारों कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवकों तक को गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। संगठन के कार्यालयों पर छापे मारे गए और दस्तावेज के साथ संपत्ति भी जब्त कर ली गई। 4 जुलाई, 1975 को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले कई अन्य संगठनों के साथ संघ को आधिकारिक रूप से ‘मीसा कानून’ के अंतर्गत प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस भारी-भरकम दृष्टिकोण के बावजूद संघ नई वास्तविकता के लिए पुनः अनुकूल होने में कामयाब रहा। संघ ने अपने स्थानीय शाखाओं की अनूठी संरचना से राष्ट्र में व्याप भय के वातावरण में भी विकेंद्रीकृत नेतृत्व के साथ जनमानस तक केंद्र सरकार की निरंकुश नीतियों का दमन और समाज में अन्य वर्ग के लोगों की सहायता से कई प्रचार-प्रसार के कार्य सफलतापूर्वक किया, जिसमें स्वयंसेवकों के अलावा सामान्य जनता का भी सरकार के प्रति रोध संघ के लिए अतुलनीय योगदान के रूप में सिद्ध हुआ। वर्ष 1975 के अंत में जेल से बाहर आकर आपने संदेश में देवरस ने लिखा-‘वर्तमान संकट वैचारिक मतभेदों से परे है। लोकतंत्र और कानून के शासन में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को हमारे मौलिक अधिकारों पर इस हमले का विरोध करने के लिए एक साथ आना चाहिए। इस निर्देश से संघ और अन्य विपक्षी समूहों के बीच सहयोग बढ़ा, जिसमें समाजवादी और मध्यमार्गी शामिल थे। देवरस ने अहिंसक प्रतिरोध के महत्व पर भी जोर दिया।

लालत गगा

कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन भारत में बढ़ते प्रदूषण के कारण जान और जहान, दोनों ही खतरे में हैं। देश की हवा में घुलते प्रदूषण का 'जहर' अनेक बार खतरनाक स्थिति में पहुंच जाना चिंता का बड़ा कारण है। प्रदूषण की अनेक बदिशों एवं हिदायतों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण की बात खोखली साबित हो रही है। यह कैसा समाज है जहां व्यक्ति के लिए पर्यावरण, अपना स्वास्थ्य या दूसरों की सुविधा-असुविधा का कोई अर्थ नहीं है। जीवन-शैली ऐसी बन गई है कि आदमी जीने के लिए सब कुछ करने लगा पर खुद जीने का अर्थ ही भूल गया। गंभीर होती इस स्थिति को यूनिसेफ और अमेरिका के स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान 'हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट' की साझेदारी में जारी रिपोर्ट ने बयां किया है। रिपोर्ट के आंकड़े करने वाले हैं, जिनमें 2021 में वायु प्रदूषण से 21 लाख भारतीयों के मरने की बात कही गई है। दुखद यह है कि मरने वालों में 1.69 लाख बच्चे हैं। निश्चय ही ये आंकड़े जहां व्याधि और चिंतित करने वाले हैं वहीं नीति-नियंताओं के लिए शर्म का विषय होना चाहिए। सरकार की नाकामियां ही हैं कि जिंदगी विषमताओं और विसंगतियों से घिरी है, कहीं से रोशनी की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। जानलेवा वायु प्रदूषण न केवल भारत, बल्कि दुनिया के लिए गंभीर समस्या है। चीन में भी इसी कालखंड में 23 लाख लोग

वायु प्रदूषण से मरे हैं। जहां तक पूरी दुनिया में इस वज्र मरने वालों की संख्या की बात है तो यह करीब 81 लाख बताई जाती है। चिंता की बात यह है कि भारत और चीन में वायु प्रदूषण से मरने वालों की संख्या के मामले में यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 54 फीसद है जो हमारे तंत्र की विफलता, गरीबी और प्रदूषण नियंत्रण में कोताही को दर्शाता है। इसमें आम आदमी की लापरवाही भी कम नहीं है। उसे पता ही नहीं होता कि किन प्रमुख कारणों से वह प्रदूषण फैला रहा है प्रश्न है कि आम आदमी एवं उसको जीवनशैली वायु प्रदूषण को इतना बेप्रवाह होकर क्यों फैलाती है? क्यों आदमी मृत्यु से नहीं डर रहा? प्रदूषण जैसी समस्याएँ नये-नये मुखौटे ओढ़ कर डरती हैं। विडम्बना तो यह है कि विभिन्न राज्य सरकारें विकट होती समस्या का हल निकालने की बजाय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपण लगाती रहती हैं। जानबूझकर प्रदूषण फैलाती हैं ताकि एक-दूसरे की छीछालेदर कर सकें। प्रदूषण के नाम पर कोरी राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली सहित उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का बेहत खतरनाक स्थिति में बने रहना चिंता में डालता है दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरु ग्राम में प्रदूषण का बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों से आने वाल पराली का धुआं होता है। पटाखों का धुआं भी समस्या है, इसके अलावा सड़कों पर लगातार बढ़ते निर्जीव वाहन, गुणवत्ता के ईंधन का उपयोग न होना, निर्माण कार्य खुले में होना, उद्योगों की घाटक गैसों व धुएं का

# आपदा के समय राज्यों को पूरी सहायता मिले

सभापति महोदय, अब तक वाद-विवाद में बाढ़ पर बहुत ध्यान दिया गया है। निःसंदेह यह एक अच्छी बात है, परंतु बाढ़ पर चर्चा करते समय सूखे को भुला दिया गया है और इसलिए मैं देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति की ओर कुछ अधिक ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं पश्चिम तटीय कोंकण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, जहां पिछले 100 वर्षों से अकाल या सूखा नहीं पड़ा। बाढ़ आई थी, पर इस बार हमने देखा कि असामान्य रूप से सूखे तथा अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी...। देश में सूखा तथा बाढ़ लगभग एक चिरकालिक समस्या बन गई है और इसलिए इनकी रोकथाम तथा बचाव के तरीकों पर हमें कुछ और चर्चा करने की जरूरत है, जिससे हम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपना सकें। ...यद्यपि बाढ़ एवं सूखा मुख्य रूप से राज्यों का विषय है, क्योंकि ये रोजमर्रा की समस्या बन गए हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे समरूप मार्गानिर्देश तैयार करें तथा राज्यों को भेजें, ताकि इनके प्रति एक समान दृष्टिकोण अपनाया जा सके तथा उस स्थिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर साधन एकत्र कर सके। जहां तक वित्तीय साधनों का संबंध है, यदि आप विभिन्न राज्य सरकारों के पास सूखे तथा बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिए उपलब्ध धनराशि को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि राज्यों के लिए संसाधन जुटाना उनकी क्षमता से बाहर है। इसलिए केंद्रीय सहायता सुलभ होनी चाहिए...। वर्तमान स्थिति क्या है? मानदंड तथा पुराने प्रतिमान के बल कल्पना शक्ति पर ही आधारित हैं; अधिकारियों को यह पता लगाने



में सूखे की स्थिति है? अधिकारियों को पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है और वे कल्पना शक्ति के सहारे ही यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है और फिर वे कहते हैं कि इस बार फसल रुपये में 50 पैसे से या 60 पैसे या 40 पैसे हैं। इसका गलत प्रभाव पड़ता है। वास्तव में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत में कई क्षेत्रों में इस पुराने मानदंड कि एक क्षेत्र विशेष में सूखे की स्थिति क्या है, के बजाय यह बेहतर होगा कि आप उस क्षेत्र विशेष में ही औसत वर्षा को लें और यदि वर्षा काफी कम हुई हो, तो गांव के अधिकारी द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट की चिंता किए बिना हमें आगे कार्रवाई करनी चाहिए। इस संबंध में आने वाली कठिनाइयों के बारे में मैं जानता हूं, हमारे वित्त मंत्री महोदय कृषि मंत्री महोदय को बताएंगे कि बैंक वालों के कारण परेशानियां पैदा होंगी। ...मैं सोचता हूं कि वित्त मंत्री चाहिए तथा पुराने मानदंडों को बिल्कुल बदल दिया जाना चाहिए। ... कुछ बड़े प्रयासों की आवश्यकता है। उनमें से एक कृपं की खुदाई करना है। इस बारे एक बड़ा दिलचस्प अनुभव है तथा यह अनुभव राजस्थान में हुआ है। ...सामान्यतया पानी 150 या 200 पुट नीचे होता है। आप पाएंगे कि सूखे की स्थिति अगर आप 700 पुट तक भी खुदाई करेंगे, तो ट्यूबवेल में कोई पानी नहीं आएगा और सारी राशि तथा सम्पद व्यवर्थ चला जाएगा।... सभी राज्यों को पर्यावरण केंद्रीय सहायता दी जानी चाहिए। यहां मेरा एक ठेर सुझाव है कि सूखे की स्थिति में कुछ ऐसे भी क्षेत्र जो बहुत पिछड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, उड़ीसा बिहार अथवा महाराष्ट्र के क्षेत्र। ...जब कभी संबंधित राज्यों को केंद्रीय सहायता दी जाती है, तो यह पर्यावरण के लिए उपयोगी होता है। अपितु सूखे की स्थिति में अवहेलना की जाती है, अपितु सूखे की स्थिति में

सरकार की ओर से स्थिति में सुधार के लिए तमाम उपाय करने की घोषणा की जाती है। गंभीर होती इस स्थिति को यूनिसेफ और अमेरिका के स्वतंत्र अनुसंधान संस्थान 'हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट' की साझेदारी में जारी रिपोर्ट ने बयां किया है। रिपोर्ट के आंकड़े करने वाले हैं, जिनमें 2021 में वायु प्रदूषण से 21 लाख भारतीयों के मरने की बात कही गई है। दुखद यह है कि मरने वालों में 1.69 लाख बच्चे हैं। निश्चय ही ये आंकड़े जहां व्याधित और चिंतित करने वाले हैं वहाँ नीति-नियताओं के लिए शर्म का विषय होना चाहिए। सरकार की नाकामियां ही हैं कि जिंदगी विषमताओं और विसंगतियों से घिरी है, कहीं से रोशनी की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। जानलेवा वायु प्रदूषण न केवल भारत, बल्कि दुनिया के लिए गंभीर समस्या है। चीन में भी इसी कालखंड में 23 लाख लोग वायु प्रदूषण से मरे हैं। जहां तक पूरी दुनिया में इस वर्ष मरने वालों की संख्या की बात है तो यह करीब 81 लाख बताई जाती है। चिंता की बात यह है कि भारत और चीन में वायु प्रदूषण से मरने वालों की संख्या के मामले में यह आंकड़ा वैश्विक स्तर पर 54 फीसद है जो हमारे तंत्र की विफलता, गरीबी और प्रदूषण नियंत्रण में कोताही को दर्शाता है। हो सकता है कि ऐसा होता भी हो, लेकिन सच यह है कि कुछ समय बाद प्रदूषण का स्तर गहराने के साथ सवाल खड़ा होता है कि आखिर, इसकी असली जड़ क्या है, और क्या सरकार की कोशिशें सही दिशा में हो पा रही हैं?

नाश्वर राशि इन उपाक्षेत पिछड़े क्षत्रा के लए निधारित करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इन पिछड़े इलाकों की सूखे के दौरान भी उपेक्षा न हो यद्यपि बाढ़ एवं सुखा मुख्य रूप से राज्यों का विषय है, क्योंकि ये रोजमर्ग की समस्या बन गए हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूँ कि वे समरूप मार्गनिर्देश तैयार करें तथा राज्यों को भेजें, ताकि इनके प्रति एक समान दृष्टिकोण अपनाया जा सके तथा उस स्थिति में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर साधन एकत्र कर सके। जहां तक वित्तीय साधनों का संबंध है, यदि आप विभिन्न राज्य सरकारों के पास सूखे तथा बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिए उपलब्ध धनराशि को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि राज्यों के लिए संसाधन जुटाना उनकी क्षमता से बाहर है। इसलिए केंद्रीय सहायता सुलभ होनी चाहिए...। वर्तमान स्थिति क्या है? मानदंड तथा पुराने प्रतिमान केवल कल्पना शक्ति पर ही आधारित हैं; अधिकारियों को यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या किसी क्षेत्र विशेष में सूखे की स्थिति है? अधिकारियों को पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है और वे कल्पना शक्ति के सहारे ही यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान स्थिति क्या है और पिछे कहते हैं कि इस बार फसल रुपये में 50 पैसे या 60 पैसे या 40 पैसे है। इसका गलत प्रभाव पड़ता है। वास्तव में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि भारत में कई क्षेत्रों में इस पुराने मानदंड कि एक क्षेत्र विशेष में सूखे की स्थिति क्या है, के बजाय यह बेहतर होगा कि आप उस क्षेत्र विशेष में हुई औसत वर्षा को लें और यदि वर्षा काफ़ी कम हुई हो, तो गांव के अधिकारी द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट की चिंता किए बिना हमें आगे कार्रवाई







